

निर्मला सीतारमण ने की घोषणा, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लपक लिया मौका

उत्तर प्रदेश अब फार्मास्यूटिकल और मेडिकल ड्रिवाइस का प्रमुख हब बनाने जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही बजट में बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। इसी कड़ी में मंगलवार को लखनऊ दिग्गज निवेशकों का जमघट लगने वाला है। लखनऊ. (जीएनएस)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को पेश किए गए बजट 2026-27 में भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की। इस कार्यक्रम के तहत अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे जैविक दवाओं, बायोसिमिलर्स और संबंधित क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस केंद्रीय घोषणा ने उत्तर प्रदेश में नई ऊर्जा भर दी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे

लपकते हुए राज्य को फार्मास्यूटिकल सांघवी (चेयरमैन, सन फार्मा), पंकज वे उद्योगपति निवेश, उत्पादन, अनुसंधान, नवाचार और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एफएसडीए आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है, जिसमें फार्मा और मेडिकल ड्रिवाइस सेक्टर को रीढ़ की हड्डी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य की निवेशक-अनुकूल नीतियां, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और विशाल उपभोक्ता बाजार इसे आकर्षक बनाते हैं।

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह बजट आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है। बायोफार्मा फंड से भारत ग्लोबल हब बनेगा और उत्तर प्रदेश इस दिशा में पहले से तैयार है। फार्मा कॉन्क्लेव से नए निवेश, साझेदारियां और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय रस्तर पर उच्च-स्तरीय नौकरियां मिलेंगी। यह आयोजन उत्तर प्रदेश को फार्मा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है, जहां केंद्रीय बजट की घोषणा और राज्य सरकार की सक्रियता मिलकर देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाएंगी।

ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की ओर बड़ा कदम



आर. पटेल (चेयरमैन, जाइडस फार्मा), रमेश जुनेजा (चेयरमैन, मैनकाइंड फार्मा), डॉ. सतीश रेड्डी (चेयरमैन, डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज), जीनल मेहता (वाइस चेयरमैन, टॉरेट फार्मा) और अयोध्या रामी रेड्डी (चेयरमैन, रामकी युप) आदि शामिल हैं।

22वीं किस्त से पहले बदल गया पीएम किसान का नियम, नहीं बनवाई ये आईडी तो रुक जाएंगे पैसे

(जीएनएस)। मध्य प्रदेश सहित देशभर के करोड़ों किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। योजना की 21 सफल किस्तों के बाद, अब 22वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे डीबीटी (अड्ड) के माध्यम से खातों में पहुंचती है। हालांकि, इस बार सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने और फर्जीवाई को रोकने के लिए 'फार्मर आईडी' (फ़ॉर्मेर आईडी) को अनिवार्य कर दिया है। यह डिजिटल पहचान पत्र अब अगली किस्त पाने के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन गया है। अगर आप भी फरवरी में आने वाली अगली किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के उठाना चाहते हैं, तो नई गाइडलाइंस को समझना आपके लिए अनिवार्य है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। सरकारी नियमों के अनुसार, हर चार महीने के अंतराल पर किस्त

जारी की जाती है। इस आधार पर 22वीं किस्त फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में आने की पूरी संभावना है। हालांकि, केंद्र सरकार ने अभी तक लाभाधिक्यों पर लगाम लगेगी। भविष्य की सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और तेजी से मिलेगा। नोट: किसानों ने अभी तक

सर्विस सेंटर' (CSC) पर जाकर मामूली शुल्क के साथ इसे बनवाया जा सकता है। ग्राम पंचायत कैम्प: कई राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष शिविर (COmps) लगाए जा रहे हैं, जहां कर्मचारी मौके पर ही किसानों की मदद कर रहे हैं। आवश्यक दस्तावेजों की सूची आईडी बनवाने के लिए किसान भाई इन दस्तावेजों को अपने पास जरूर रखें: आधार कार्ड: पहचान के प्रमाण के लिए। भूमि दस्तावेज: जमीन की खतौनी या खसरा की कॉपी। मोबाइल नंबर: आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है ताकि ओटीपी वेरिफिकेशन हो सके। किसानों के लिए जरूरी सलाह अगली किस्त आने में अब बहुत कम समय बचा है। यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है या अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, तो तुरंत इस काम को प्राथमिकता दें। ऑनलाइन: किसान स्वयं आधिकारिक सरकारी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उरउ सेंटर: अपने नजदीकी 'कॉमन



मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का जिला कलेक्टरों से आह्वान- आगामी मानसून से पहले ही जल संचय के कार्यों का अग्रिम आयोजन कर बरसाती पानी के अधिकाधिक संचय और संग्रह के जरिए जल संचय के क्षेत्र में गुजरात का नेतृत्व बनाए रखें

गांधीनगर, 03 फरवरी : राज्य में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान के कामकाज की सर्वगाही समीक्षा के लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक हुई। इस समीक्षा बैठक में दिल्ली से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और जल शक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री वी.एल. कांतारव और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ गांधीनगर से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, मुख्य सचिव श्री एम.के. दास और वरिष्ठ सचिव शामिल हुए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्य के बनावसकांठा, कच्छ और राजकोट जिले के कलेक्टरों के प्रेजेंटेशन सहित विभिन्न जिला कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में 'जल संचय जनभागीदारी 2.0' अभियान की प्रगति और आगामी आयोजन की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने इस समीक्षा बैठक में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और उनका समाधान देने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए 'कैच द

रेन' अभियान और जल संचय की राष्ट्रव्यापी मुहिम का अधिक से अधिक लाभ गुजरात को मिले। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला

संदर्भ में यह सुनिश्चित करें कि इसका भी उपयोग जिलों में जल संचय के कार्यों के लिए हो। मुख्यमंत्री ने बैठक में जल संचय के व्यापक कार्यों को तेजी से शुरू करने का निर्देश दिया ताकि केंद्र सरकार द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना के अंतर्गत राज्य को आवंटित 553 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का संपूर्ण उपयोग मार्च-2026 से पहले हो जाए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कहा कि जल संचय-जल संग्रह क्षेत्र में गुजरात ने जो कार्य किया है, वह देश में मॉडल बन गया है। उन्होंने कहा कि पुराने बोर रिचार्ज करने की 70 फीसदी राशि केंद्र सरकार द्वारा देने के निर्णय से बड़ा लाभ हुआ है। उन्होंने जल संचय के कार्यों में अधिक संख्या में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को जोड़ने के लिए एक सूची बनाकर उन्हें



कलेक्टरों को सीख देते हुए कहा कि वे भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिलों में बरसाती पानी के संग्रहण और संचयन के कार्य करें। ये सभी ऐसे जनहित के कार्य हैं, जिनसे कर्तव्य निभाने के कार्य संतोष के साथ-साथ आत्मसंतोष भी मिलता है। मुख्यमंत्री ने ऐसा वातावरण बनाने की हिमायत की जिसमें राज्य के जिलों के बीच जल संचय-जनभागीदारी अभियान के कार्यों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो और जिन जिलों में जल संचय का काम कम हुआ हो, उन्हें भी अधिक कार्य करने का बल मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विधायक को जल संचय-जल संग्रह के कार्यों के लिए 50 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है, इस

जिन्हें आने वाले दिनों में भरा जाएगा। इसके अलावा 181 गांवों में प्रारंभिक विद्यालय नहीं हैं, वहां स्कूल शुरू किए जाएंगे और बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। जिले में 1200

नर्मदा में राजनीतिक भूचाल, भाजपा-कांग्रेस के 1000 से ज्यादा लोग आप में शामिल हुए

अहमदाबाद/नर्मदा/भरुक/ जिले के चौकदा गांव में अरुण की भव्य परिवर्तन सभा आयोजित की गई, जिसमें अरुण विधायक चैतर वसावा, दिल्ली से आए विधायक अखिलेश त्रिपाठी ने उपस्थित दर्ज कराई थी। विधायक और दिल्ली के विधायक अखिलेश त्रिपाठी की मौजूदगी में भाजपा-कांग्रेस के 1000 से भी ज्यादा लोग अरुण में शामिल हुए थे। साथ ही साथ इस सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और अरुण को समर्थन दिया। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा के विधायक चैतर वसावा ने जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी समाज के अधिकारों, विकास और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दों पर भाजपा सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में उन्हे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और पार्टी आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चैतर वसावा ने कहा कि आदिवासियों को संवैधानिक अधिकार वर्षों से केवल कागजों पर ही रहे हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निश्चित रूप से जमीन पर लागू किया जाएगा। सरकार बनते ही आदिवासी समाज की ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वन अधिकार कानून के तहत जिन लोगों के अधिकार लंबित हैं, उन्हें उनके अधिकार दिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 505 शिक्षकों के पद खाली हैं, (जीएनएस)। दिल्ली में आज 4 फरवरी को क्या कुछ बड़ा होने वाला है, अगर आप एक नजर में जानना चाहते हैं तो यह रिपोर्ट आपके लिए है। राजधानी से जुड़ी अपराध, मेट्रो, राजनीति, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोर्ट से आई उन खबरों को हम आसान भाषा में समझा रहे हैं, जो सीधे आपके रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती हैं। साल 2026 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में लापता लोगों के आंकड़े डराने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार जनवरी के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए। इनमें से 235 को खोज लिया गया, लेकिन 572 लोग अब भी लापता हैं। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें बच्चों की संख्या काफी ज्यादा है। लापता बच्चों में 137 नाबालिग शामिल हैं, जिनमें 120 लड़कियां हैं। यानी सबसे ज्यादा किशोरियां गायब हो रही हैं। उम्र के हिसाब से देखें तो 12 से 18 साल के बच्चों के मामले सबसे अधिक हैं। सिर्फ इसी आयु वर्ग में 169 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 121 अब तक नहीं मिले। यह आंकड़े दिल्ली में बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। दिल्ली मेट्रो फेज-4 के पूरा होते

संस्थाओं में सत्ता प्राप्त किए बिना आदिवासी समाज की समस्याओं का समाधान करना कठिन है। उन्होंने 2027 में पूरे गुजरात में परिवर्तन करने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो, सड़क हो या मैदान—जहां भी जरूरत पड़े, वे जनता की आवाज उठाते हैं, जो भाजपा सरकार को परसंद नहीं है। भाजपा के कुछ नेता और उनके समर्थक लोगों पर दबाव डालने के लिए फोन कर रहे हैं और लोगों को डेडियापाड़ा न आने देने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह शक्ति और हिम्मत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे साथ सरपंच, जिला प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग तथा माता-पिता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसी जनसमर्थन के कारण मैं इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। मनरेगा सहित विभिन्न मुद्दों पर नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती—ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक वन अधिकारों पर स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज इस जंगल में आदिवासी से निवास करता आया है और लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज पर उनका अधिकार है। इस मुद्दे पर वन विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों पर अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात

दिल्ली में हर दिन 27 लोग लापता, मेट्रो पर बड़ा अपडेट,

हो राजधानी और आसपास के शहरों की तस्वीर बदलने वाली है। इस फेज में 6 नए कॉरिडोर और 84 नए स्टेशन जुड़ेंगे। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा मार्क एक्सप्रेसजैसे हिस्सों में ट्रायल रन शुरू हो चुका है। फेज-4 पूरा होने पर इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो जाएगी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली के किसी भी कोने तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक सभी लाइनें चालू हो जाएं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी रकम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को अहम सुनवाई होने जा रही है। इस

मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर विचार किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर सुनवाई का फैसला करेगी। संभावना जताई जा रही है कि

मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर जोरदार तरीके से गुंजा

डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन नई दिल्ली, डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन, दिल्ली एनसीआर द्वारा राजेंद्र भवन में आयोजित वार्षिक मेल-मिलाप कार्यक्रम में डोगरी-पहाड़ी भाषा और संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और एकता का स्वर जोरदार तरीके से गुंजा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के सदर-ए-रियासत यह चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. कर्ण सिंह ने कहा कि डोगरा समाज को कांगड़ा और चंबा जैसे पड़ोसी पहाड़ी-भाषी क्षेत्रों के साथ मिलकर अपनी सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुभाषिक होना समय की जरूरत है, लेकिन मातृभाषा की अयदेखी नहीं की जा सकती। यदि नई पीढ़ी को डोगरी बोलने के लिए प्रेरित नहीं किया गया तो यह भाषा आने वाले समय में संकट में पड़ सकती है। डॉ.सिंह ने

प्रगतिशील और दूरदर्शी बने रहने की अपील की। उन्होंने इस आयोजन के लिए सुदेश डोगरा और समस्त आयोजक टीम को बधाई भी दी। लोकप्रिय डोगरी-हिमाचली लोकगीत हम्मारे निं मेरिये, जम्मू ए दी राहे, चंबा कितनी क दूरह में कथित ज्योति गुप्ता सहित अन्य कलाकारों ने भी भाग लिया। एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर जम्मू के प्रमुख साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठनों की चुप्पी पर निराशा व्यक्त की, जबकि लोकगीतों की सांस्कृतिक चिंताओं की हिफाजत में आवाज उठाने वाले हिमाचली

कलाकारों की सराहना की। वरिष्ठ पत्रकार और भाषा कार्यकर्ता रमन केसर ने कहा कि लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ पश्चिमी पहाड़ी और डोगरी को अलग-अलग दिखाने का प्रयास है, जिसका एसोसिएशन रचनात्मक और सशक्त ढंग से विरोध करेगी। इस अवसर पर रोहित महाजन, क्लास्टर हेड, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को ट्रॉफियां भेंट कर के सम्मानित किया। कार्यक्रम के आयोजन में कैलाशपति शर्मा, सुदेश डोगरा, जगदीश शर्मा, कुलवीर सिंह, कर्नल सुनील शर्मा, नेहा शर्मा, सतपाल शर्मा और बोधराज ठाकुर, राज रैना जी का विशेष योगदान रहा। डोगरा वेलफेयर एसोसिएशन पिछले चार वर्षों से लोहड़ी के अवसर पर लगातार यह आयोजन कर रही है। एसोसिएशन ने स्वयं को राजनीति से दूर रखा हुआ है और समाजी-सांस्कृतिक कार्यों में लगे हुई है।

कहा कि देश-विदेश से कोई भी नेता आए, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों में जागरूकता फैलाने, लोगों को एकजुट करने और लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने का काम करती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा हो, सड़क हो या मैदान—जहां भी जरूरत पड़े, वे जनता की आवाज उठाते हैं, जो भाजपा सरकार को परसंद नहीं है। भाजपा के कुछ नेता और उनके समर्थक लोगों पर दबाव डालने के लिए फोन कर रहे हैं और लोगों को डेडियापाड़ा न आने देने के प्रयास करते हैं। लेकिन यह शक्ति और हिम्मत केवल मेरी व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि मेरे साथ सरपंच, जिला प्रमुख, उपप्रमुख, कार्यकर्ता, युवा, बुजुर्ग तथा माता-पिता का आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। इसी जनसमर्थन के कारण मैं इतनी बड़ी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। मनरेगा सहित विभिन्न मुद्दों पर नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती—ऐसा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इसका जवाब जनता आगामी तालुका और जिला पंचायत चुनावों में देगी। उन्होंने आदिवासी समाज के पारंपरिक वन अधिकारों पर स्पष्ट कहा कि आदिवासी समाज इस जंगल में आदिवासी से निवास करता आया है और लकड़ी, बांस तथा अन्य वन उपज पर उनका अधिकार है। इस मुद्दे पर वन विभाग को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि आदिवासियों पर अन्याय हुआ तो वे सड़क पर उतरेंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात



रन शुरू हो चुका है। फेज-4 पूरा होने पर इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर 40 से ज्यादा हो जाएगी। गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद से दिल्ली के किसी भी कोने तक सीधी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक सभी लाइनें चालू हो जाएं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी रकम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4 फरवरी को अहम सुनवाई होने जा रही है। इस



मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर विचार किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस पर सुनवाई का फैसला करेगी। संभावना जताई जा रही है कि

सम्पादकीय

कूटनीतिक कौशल के सहारे एक अच्छी डील कर सका भारत

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का यह दावा कि भारत बिना वृषि और दुग्ध क्षेत्र के साथ बिना किसी समझौते के अमेरिका के साथ एक अच्छे टैरिफ करार पर सहमति बनी है। जबकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी मंगलवार को ही राजग संसदीय दल की बैठक में सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौता एक बड़ा पैसला है जो हर देशवासी के लिए लाभदायक होगा। लगे हाथ उन्होंने यह भी कह दिया कि उनकी सरकार हमेशा राष्ट्र के हित में काम करती है।

दरअसल मोदी सरकार जिस तरह अमेरिका के साथ सौदेबाजी करने के लिए अपनी शर्तों पर अड़ी वह तो निमित्त रूप से इस बात का परिचायक है कि सरकार ने भी धैर्य का परिचय दिया, भारत वशियों ने भी धैर्य एवं संयम से काम लिया। भारतीय उत्पादकों को अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ में अतार्किक बढ़ोतरी के कारण बहुत नुकसान हुआ। किन्तु उन्हें इस बात का भरोसा था जब भी समझौता होगा तो अच्छा ही होगा। भारत सरकार अमेरिका स्थित भारतीय राजदूतावास और भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने जिस सत्रियता के साथ अमेरिकी प्राशासन के साथ समन्वय स्थापित किया और उन्हें हकीकत महसूस कराई, उसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने न सिर्फ दंडात्मक 25 प्रतिशत टैरिफ हटाया बल्कि 25 प्रतिशत से भी कम करके 18 प्रतिशत कर दिया जबकि भारत ने अमेरिका की शर्तों को ठुकराकर रूस से तेल खरीदना बंद भी नहीं किया।

सच तो यह है कि भारत ने बजट में जिस तरह जीवन रक्षक दवाओं और चमड़ों पर आयात कर कम किया था, उसी का परिणाम है कि भारतीय ग्राहक और उत्पादक दोनों ही राहत महसूस करने लगे। साथ ही जिन देशों से दवाएं एवं जूते आदि आयात किए जाते हैं उन देशों के उत्पादकों ने भी राहत की सांस ली। सरकार ने तो बजट में इस बात की तैयारी कर ली थी कि वैसे टैरिफ आतंक की चुनौती से निपटा जा सकता है किन्तु लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने न सिर्फ अमेरिका से वृत्तीयक रिश्ता कायम रखा बल्कि ट्रंप द्वारा ज्यादा टैरिफ लगाए जाने के बाद न सिर्फ रूस से फायदा लिया बल्कि चीन को भी इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह भारत के साथ व्यापार संतुलन सुधारने के लिए भारतीय उत्पादों का आयात बढ़ाए। चीन ने भारत के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए न सिर्फ अपने टैरिफ को कम किया बल्कि रेयर अर्थ मिनरल देने का भी वादा किया। रूस ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत बनाते हुए व्यापारिक क्षेत्र को व्यापक बनाया। इसी वजह से भारत ने रूस से बहुत ज्यादा सोना खरीदा जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में न सिर्फ स्थिरता आई मजबूती आई बल्कि दुनिया के उन देशों और क्षेत्रीय संगठनों को नई दिल्ली की वृत्तीय और व्यापार सहयोग की रणनीतिक सहभागिता विश्वसनीय प्रतीत हुई। इसी वजह से एफटीए की जो सौदेबाजी प्राविद्या वर्षों से यूरोपीय यूनियन लटकाए पड़ा था, उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए उतावला हो गया।

बहरहाल अमेरिका के साथ भारत के टैरिफ का मुद्दा भले ही सुलझ गया किन्तु अब जो ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में भारत की भूमिका एक तरफ वुआं दूसरी तरफ खाई की होने वाली है, वह निमित्त रूप से बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका चाहता है कि भारत हर बार की तरह इस बार भी ब्रिक्स मुद्दा में व्यापार की प्राविद्या शुरू न करके वाशिंगटन डीसी की बादशाहत कायम रखने में मदद करेगा जबकि भारत के साथ मिल कर चीन और रूस विश्व व्यापार में डालर की भूमिका को सीमित करना चाहते हैं।

संसद में उपस्थिति, भागीदारी, बहस और जवाबदेही... तारीफ में पीएम मोदी के ये शब्द किस सांसद के लिए? बताया सीखने की मिसाल

संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं है यह लोकतंत्र की आत्मा और आम जनता की शक्ति का केंद्र है। इसी आत्मा और आम लोगों के लोकतांत्रिक ताकत को मजबूत करने वाला एक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले दिया। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे यह सीखना चाहिए कि संसद में परफॉर्मेंस कैसे की जाती है।

नई दिल्ली. (जीएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की मीटिंग में झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की खुलकर तारीफ की। पीएम ने कहा कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर आखिर तक मौजूद रहते हैं। हर महत्वपूर्ण डिस्क्शन में भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ बहस करते

पीएम ने 'दिव्यांग' शब्द देकर बदली देश की सोच, दिव्यांगजनों को बताया राष्ट्र निर्माण के साझे सहभागी: सिंधिया

अशोक नगर / धोपाला, (जीएनएस)।

3 फरवरी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री तथा गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने संसदीय क्षेत्र के अशोकनगर जिले के मरूप गांव में आयोजित भव्य 'दिव्यांगजन एवं वृद्धजन सहायक उपकरण वितरण शिविर' में संवेदना और सम्मान के संकल्प को साकार किया।

इस अवसर पर उन्होंने 1237 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को आधुनिक सहायक उपकरण वितरित करते हुए कहा कि यह आयोजन सिर्फ उपकरण वितरण नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और

हैं। यह मिसाल है कि संसद में कैसे प्रभावी योगदान दिया जा सकता है। सभी सांसदों को उनसे सीखना चाहिए। पीएम मोदी ने ये बातें 3 फरवरी 2026 की मीटिंग में कही जहां बजट सेशन और संसदीय कार्यों पर चर्चा हुई। जानकारों की नजर में पीएम मोदी की निशिकांत दुबे को लेकर की गई यह टिप्पणी केवल किसी एक सांसद को साराहना नहीं, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी जिम्मेदारियों की याद दिलाने वाला संदेश है।

संसद में मौजूद रहना क्यों मायने रखता है

जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया वह थी- संसद में सांसदों की उपस्थिति। उन्होंने कहा कि निशिकांत दुबे संसद सत्र शुरू होने से लेकर अंत तक सदन में मौजूद रहते हैं। संसदीय लोकतंत्र में उपस्थिति केवल औपचारिकता नहीं होती। यह महत्वपूर्ण डिस्क्शन में भाग लेते हैं और पूरी रिसर्च के साथ बहस करते

सामाजिक समावेशन की दिशा में एक सशक्त कदम है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 'ग्वालियर-चंबल अंचल में सेवा सिंधिया परिवार के लिए शासन का विषय नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से निभाया जा रहा एक पवित्र कर्तव्य रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अशोकनगर में 1456, गुना में 1745 और शिवपुरी में 5250 सहित कुल पूरे संसदीय क्षेत्र में 8,240 दिव्यांगजनों तक सेवा पहुंचाने का लक्ष्य किसी आंकड़े तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 8,240 परिवारों की आशा, गरिमा और भविष्य से जुड़ा संकल्प है। सिंधिया ने रेखांकित किया कि

प्रतिनिधित्व करने का दायित्व लिया है, उनका सदन में रहना ही उसकी प्रतिबद्धता को बताता है। पीएम मोदी



का यह संदेश साफ है कि संसदीय लोकतंत्र में संसद में खाली कुर्सियां नहीं सक्रिय जनप्रतिनिधि चाहिए। बहस और भागीदारी से बनती है संसद की ताकत पीएम मोदी के शब्दों को और

गहराई से समझें तो निशिकांत दुबे की चर्चा करते हुए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि संसद की गरिमा केवल

नहीं, कर्तव्य भी है। जब सांसद चर्चा में भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और तर्क रखते हैं, तभी जन कल्याणकारी नीतियां बनती हैं और बेहतर परिणाम सामने आते हैं। पीएम मोदी का यह संदेश उन सांसदों के लिए भी है जो संसद को बहस का मंच नहीं केवल उपस्थिति रजिस्टर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित (अंडरलाइन) किया कि निशिकांत दुबे हर बहस से पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं। पीएम मोदी यह टिप्पणी मौजूदा राजनीति में बेहद अहम है। संसद में भावनात्मक भाषणों से ज्यादा तथ्य, आंकड़े और अध्ययन की जरूरत होती है। रिसर्च आधारित बहस न सिर्फ सरकार को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनाती है। पीएम मोदी का यह संदेश बताता है कि संसद में प्रभाव बनाने का रास्ता शोर नहीं बल्कि पुष्टा रिसर्च और बहस करना संसदीय अधिकार ही

नहीं, कर्तव्य भी है। जब सांसद चर्चा में भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और तर्क रखते हैं, तभी जन कल्याणकारी नीतियां बनती हैं और बेहतर परिणाम सामने आते हैं। पीएम मोदी का यह संदेश उन सांसदों के लिए भी है जो संसद को बहस का मंच नहीं केवल उपस्थिति रजिस्टर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित (अंडरलाइन) किया कि निशिकांत दुबे हर बहस से पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं। पीएम मोदी यह टिप्पणी मौजूदा राजनीति में बेहद अहम है। संसद में भावनात्मक भाषणों से ज्यादा तथ्य, आंकड़े और अध्ययन की जरूरत होती है। रिसर्च आधारित बहस न सिर्फ सरकार को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनाती है। पीएम मोदी का यह संदेश बताता है कि संसद में प्रभाव बनाने का रास्ता शोर नहीं बल्कि पुष्टा रिसर्च और बहस करना संसदीय अधिकार ही

नहीं, कर्तव्य भी है। जब सांसद चर्चा में भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और तर्क रखते हैं, तभी जन कल्याणकारी नीतियां बनती हैं और बेहतर परिणाम सामने आते हैं। पीएम मोदी का यह संदेश उन सांसदों के लिए भी है जो संसद को बहस का मंच नहीं केवल उपस्थिति रजिस्टर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित (अंडरलाइन) किया कि निशिकांत दुबे हर बहस से पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं। पीएम मोदी यह टिप्पणी मौजूदा राजनीति में बेहद अहम है। संसद में भावनात्मक भाषणों से ज्यादा तथ्य, आंकड़े और अध्ययन की जरूरत होती है। रिसर्च आधारित बहस न सिर्फ सरकार को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनाती है। पीएम मोदी का यह संदेश बताता है कि संसद में प्रभाव बनाने का रास्ता शोर नहीं बल्कि पुष्टा रिसर्च और बहस करना संसदीय अधिकार ही

नहीं, कर्तव्य भी है। जब सांसद चर्चा में भाग लेते हैं, सवाल पूछते हैं और तर्क रखते हैं, तभी जन कल्याणकारी नीतियां बनती हैं और बेहतर परिणाम सामने आते हैं। पीएम मोदी का यह संदेश उन सांसदों के लिए भी है जो संसद को बहस का मंच नहीं केवल उपस्थिति रजिस्टर समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी रेखांकित (अंडरलाइन) किया कि निशिकांत दुबे हर बहस से पहले पूरी रिसर्च करके आते हैं। पीएम मोदी यह टिप्पणी मौजूदा राजनीति में बेहद अहम है। संसद में भावनात्मक भाषणों से ज्यादा तथ्य, आंकड़े और अध्ययन की जरूरत होती है। रिसर्च आधारित बहस न सिर्फ सरकार को मजबूत करती है, बल्कि विपक्ष को भी जिम्मेदार बनाती है। पीएम मोदी का यह संदेश बताता है कि संसद में प्रभाव बनाने का रास्ता शोर नहीं बल्कि पुष्टा रिसर्च और बहस करना संसदीय अधिकार ही

पीएम मोदी की यह तारीफ जवाबदेही के व्यापक सिद्धांत से भी जुड़ी है। संसद में सवाल पूछना, नीतियों पर चर्चा करना और सरकार से जवाब मांगना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जब सांसद सदन में सक्रिय रहते हैं, तब कार्यपालिका भी सतर्क रहती है। प्रधानमंत्री की यह टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि संसद की मजबूती ही लोकतंत्र की मजबूती है, और यह मजबूती सांसदों की सक्रियता से आती है।

पाटी के भीतर संदेश और राजनीतिक अर्थ राजनीतिक दृष्टि से देखें तो निशिकांत दुबे के लिए पीएम मोदी की यह तारीफ भाजपा और एनडीए के भीतर भी एक स्पष्ट संकेत है। पीएम मोदी यह बताना चाहते हैं कि पाटी नेतृत्व सांसदों के व्यवहार, अनुशासन और संसदीय भूमिका को गंभीरता से देखता है। यह केवल लोकप्रियता की राजनीति नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारी की राजनीति का संकेत है।

'प्रेग्नेंसी में सास ने पेट में लात मारी, मेरी खूब पिटाई की', करिश्मा कपूर का शॉकिंग खुलासा, छलका मेंटल दर्द

(जीएनएस)। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के दिवंगत पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर (२९८८८ डेस४१) की संपत्ति को लेकर अब एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। कथित तौर पर 30,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर अधिकार को लेकर परिवार के अलग-अलग पक्ष आमने-सामने हैं। मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है, जहां इस हाई-प्रोफाइल केस में समन जारी किए गए हैं।

किन पक्षों के बीच है टकराव? इस विवाद में मुख्य रूप से तीन पक्ष सामने आए हैं- संजय कपूर की मां रानी सुरिंदर कपूर संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव करिश्मा कपूर से हुए संजय कपूर के दोनों बच्चों (बेटी समायरा और बेटा कियान) रानी कपूर ने अदालत में दायर याचिका में कुल 22 लोगों के खिलाफ आरोप लगाए हैं।



आरके फैमिली ट्रस्ट पर उठे सवाल -याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरके फैमिली ट्रस्ट के जरिए पारिवारिक संपत्ति को ट्रांसफर किया गया जिसकी जानकारी और सहमति रानी कपूर को नहीं दी गई थी। उनके अनुसार ये ट्रस्ट अवैध है और कानून के खिलाफ बनाकर संपत्ति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की गई। रानी कपूर ने अदालत से मांग की है कि इस ट्रस्ट को निरस्त किया जाए और संपत्ति के हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया की जांच हो।

-दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को बड़ी खबरें बनी थीं। -हाल के घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर वो पुराने आरोप चर्चा में हैं, जिनमें करिश्मा कपूर ने अपने पूर्व पति संजय कपूर और सास रानी कपूर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। -ये सभी बातें उस समय करिश्मा कपूर द्वारा इंटरव्यू और कानूनी दस्तावेजों में किए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों पर दूसरी तरफ से अलग-अलग समय पर अपनी सफाई भी दी गई थी। -करिश्मा कपूर ने अपने तलाक के दौरान दायर शिकायतों और इंटरव्यू में कहा था कि शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन वैसा नहीं रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। उनके मुताबिक उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा जाता था और छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था। करिश्मा कपूर ने दावा किया था कि घर का माहौल उनके लिए अस्थिर और तनावपूर्ण हो गया था, जहां उन्हें सम्मान की बजाय ताने और दबाव झेलना पड़ता था।

को समन जारी किए हैं। अब अदालत में दस्तावेजों, ट्रस्ट की वैधता और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कानूनी जांच होगी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर को दर्दनाक शादी -इस मामले के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी भी फिर से सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें कि करिश्मा और संजय कपूर की शादी, तलाक और उससे जुड़े आरोप उस दौर में मीडिया

का बड़ी खबरें बनी थीं। हाल के घटनाक्रमों के बीच एक बार फिर वो पुराने आरोप चर्चा में हैं, जिनमें करिश्मा कपूर ने अपने पूर्व पति संजय कपूर और सास रानी कपूर पर मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। ये सभी बातें उस समय करिश्मा कपूर द्वारा इंटरव्यू और कानूनी दस्तावेजों में किए गए आरोपों पर आधारित हैं। इन आरोपों पर दूसरी तरफ से अलग-अलग समय पर अपनी सफाई भी दी गई थी। करिश्मा कपूर ने अपने तलाक के दौरान दायर शिकायतों और इंटरव्यू में कहा था कि शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन वैसा नहीं रहा था जैसा उन्होंने सोचा था। उनके मुताबिक उन्हें लगातार मानसिक दबाव में रखा जाता था और छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था। करिश्मा कपूर ने दावा किया था कि घर का माहौल उनके लिए अस्थिर और तनावपूर्ण हो गया था, जहां उन्हें सम्मान की बजाय ताने और दबाव झेलना पड़ता था।

को समन जारी किए हैं। अब अदालत में दस्तावेजों, ट्रस्ट की वैधता और संपत्ति के स्वामित्व को लेकर कानूनी जांच होगी। करिश्मा कपूर और संजय कपूर को दर्दनाक शादी -इस मामले के चलते बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की निजी जिंदगी भी फिर से सुर्खियों में आ गई है। आपको बता दें कि करिश्मा और संजय कपूर की शादी, तलाक और उससे जुड़े आरोप उस दौर में मीडिया

धोनी ने बताया इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक टीम का नाम, जीतने को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

(जीएनएस)। क्रिकेट के गलियारों में आजकल टी20 वर्ल्ड कप की ही चर्चा है। यह टूर्नामेंट इसलिए खास है क्योंकि इसकी मेजबानी भारत खुद कर रहा है। लेकिन इस उत्साह के बीच 'केप्टन कूल' महेंद्र सिंह धोनी के एक हालिया वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। धोनी ने टीम इंडिया की जीत की संभावनाओं पर ऐसी बात कही है जिसे हर क्रिकेट प्रेमी को जानना चाहिए। जितन सपू के साथ बातचीत के वायरल वीडियो में धोनी ने भारतीय टीम की ताकत का बारीकी से विश्लेषण किया है। धोनी का मानना है कि भारतीय पिचों पर टीम इंडिया को



का सपोर्ट खिलाड़ियों में जो ऊर्जा भरता है, वह किसी टॉनिक से कम नहीं होता। माही ने मौजूदा टीम के बेखोफ

अंदाज की तारीफ की है। उन्होंने संकेत दिया कि आज के युवा खिलाड़ी नाम देखकर नहीं, बल्कि गैद देखकर शॉट लगाते हैं, जो कि टी 20 जैसे छोटे फॉर्मेट की सबसे पहली जरूरत है। धोनी ने जोर दिया कि टीम इंडिया में अब ऑलराउंडर्स और गहराई वाली बल्लेबाजी है, जो किसी भी मुश्किल परिस्थिति से मैच निकाल सकती है। माही ने इस टीम को सबसे खतरनाक टीम बताया है।

धोनी के इस बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या 2026 के महाकुंभ में वह टीम इंडिया के साथ किसी नई भूमिका में नजर आएंगे? हालांकि धोनी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन क्रिकेट जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ टीम के बहुत काम आ सकती है। भारतीय फैंस अभी भी 2007 को उस जीत को नहीं भूलें हैं जब धोनी की कप्तानी में भारत पहला टी20 वर्ल्ड चैंपियन बना था। अब करीब दो दशक बाद, जब टूर्नामेंट फिर से दहलीज पर है, तो धोनी के शब्द फैंस के लिए किसी गारंटी से कम नहीं लग रहे।

सोना-चांदी 40,000 रुपये तक महंगा! आम आदमी की बढ़ी मुसीबत, जानिए अचानक क्यों लौटी तेजी?

(जीएनएस)। पिछले पांच दिनों में सोना और चांदी की कीमतों में ऐसी तेज गिरावट देखी गई कि निवेशकों के हाथ-पांव फूल गए। चांदी जहां अपने रिकॉर्ड हाई 4.20 लाख रुपये प्रति किलो से फिसलकर करीब 2 लाख रुपये की गिरावट की ओर बढ़ गई थी, वहीं सोना भी 1.93 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से टूटकर करीब 1.43 लाख रुपये तक आ गया था। लगातार तीन सत्रों की भारी बिकवाली ने बाजार का मूड पूरी तरह नेगेटिव कर दिया था। लेकिन 3 फरवरी 2026 को तत्काल अचानक बदल गई। वायदा बाजार में सोने और चांदी ने जोरदार वापसी की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 मार्च 2026

डिलिवरी वाली चांदी में शाम करीब 7 बजे जबरदस्त तेजी दिखाई। कीमत एक झटके में 40,000 रुपये से ज्यादा उछल गई। खबर लिखे जाने तक चांदी 2,74,558 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। दिन का हाई 2,78,000 रुपये और लो लेवल 2,45,711 रुपये रहा। इससे पहले चांदी 2,36,261 रुपये पर बंद हुई थी। सोने की बात करें तो अप्रैल डिलिवरी वाला सोना 7,923 रुपये यानी करीब 5.5 प्रतिशत उछलकर 1,51,914 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गौर करने वाली बात यह

है कि इससे पहले तीन सत्रों में सोना लगभग 40,000 रुपये या 22 प्रतिशत तक टूट चुका था। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में भी सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार रिकवरी देखी गई। चांदी 24,000 रुपये की छलांग लगाकर 2.84 लाख रुपये प्रति किलो पहुंच गई। वहीं 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 5,000 रुपये बढ़कर 1,57,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, इस उछाल के पीछे तीन बड़े कारण हैं। पहला, भारी गिरावट के बाद

सोना-चांदी सस्ते स्तर पर पहुंचे, जिससे निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। दूसरा, दुनिया भर के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं, जिससे कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिला। तीसरा, अमेरिका में बढ़ते राजकोषीय जोखिम और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर उठते सवालियों के बीच सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की मांग फिर से बढ़ी है। आगे क्या रहेगा ट्रेंड? जानकारों का मानना है कि बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन गिरावट के बाद आई तेजी बताती है कि सोना-चांदी अभी भी निवेशकों की पहली पसंद बने हुए हैं।

3 भारतीय खिलाड़ी बेंच पर बैठे रह जाएंगे, टी 20 वर्ल्ड कप इलेवन में मौका मिलना लगभग नामुमकिन

(जीएनएस)। टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में प्लेइंग इलेवन का चुनाव सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि फॉर्म, कॉम्बिनेशन और रोल ब्लैरिटी पर होता है। भारतीय टीम इस बार बेहद संतुलित नजर आ रही है, लेकिन इसी संतुलन की वजह से कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें पूरे टूर्नामेंट के दौरान बेंच पर बैठकर ही टीम का सफर देखना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं उन तीन खिलाड़ियों की, जिनका नाम स्क्वाड में तो है, लेकिन प्लेइंग इलेवन में जगह मिलना बेहद मुश्किल दिख रहा है। उन तीन प्लेयर्स के बारे में आपको भी जानना चाहिए, इससे टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर काफी हद तक एक आइडिया लग जाएगा। 1. संजू सैमसन संजू सैमसन का नाम आते ही फैंस को उम्मीद बंधती है, लेकिन हालिया फॉर्म ने उनकी दावेदारी को

कमजोर कर दिया है। टी20 फॉर्मेट में लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन न कर पाना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या प्लेइंग इलेवन का दरवाजा लगभग बंद नजर आता है और उनके लिए यह वर्ल्ड कप बेंच पर बैठकर ही गुजर सकता है। 2. हर्षित राणा हर्षित राणा ने घरेलू क्रिकेट और क्लब में अपनी तेज गेंदबाजी से जरूर क्लब में अपनी तेज गेंदबाजी से जरूर प्रभावित किया है, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप जैसे मंच पर टीम संयोजन ज्यादा अहम हो जाता है। भारतीय टीम में पहले से ही हार्दिक पांड्या और शिवम

दुबे जैसे ऑलराउंडर मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी का संतुलन देते हैं। ऐसे में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को मौका मिलना बेहद कठिन है। टीम जरूरत के हिसाब से ऑलराउंड ऑप्शन को तरजीह देगी, जिससे हर्षित का रोल बैकअप तक ही सीमित रह सकता है। 3. वाशिंगटन सुंदर : वाशिंगटन सुंदर का मामला सबसे ज्यादा कॉम्प्लिटेड है। टीम में पहले से अक्षर पटेल मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी, फील्डिंग और गेंदबाजी तीनों में ज्यादा प्रभावी विकल्प माने जा रहे हैं। वहीं स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और चरण चक्रवर्ती जैसे प्रॉपर विकेट-टैकिंग स्पिनर टीम की पहली पसंद हैं। ऐसे में सुंदर की उपयोगिता सीमित हो जाती है। परिस्थितियां बेहद खराब न हों, तो उनके लिए प्लेइंग इलेवन में जगह बनाए लगभग असंभव नजर आता है।



लखनऊ की हमलावर गाय समेत 5 मवेशी पकड़े गए, सामने आए इनके मालिकों के नाम

(जीएनएस)। लखनऊ के चौपटिया इलाके में जिस गाय द्वारा लड़की पर हमले का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था उसे नगर निगम की टीम ने पकड़ लिया है। इसके साथ ही नगर निगम ने और भी गायें पकड़ी हैं और उनके मालिकों की पहचान की है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के चौपटिया इलाके में एक लड़की के ऊपर हमला करने वाली गाय को नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम ने पकड़ लिया है। नगर निगम ने गाय के मालिकों की भी पहचान कर ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर भी दे दी है। बता दें कि एक दिल दहलाने वाली घटना में सड़क पर खुली घूम रही एक गाय ने एक लड़की पर अचानक हमला कर दिया था। यह पूरी घटना

पास में लगे उड्डर कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि गाय



अचानक लड़की की ओर दौड़ती है, जिससे घबराकर लड़की भागने की कोशिश करती है, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वह सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद गाय उसे पैरों तले रौंदने

लगती है। घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई और बड़ी मुश्किल से गाय को भगाकर

लड़की को उसके चंगुल से छुड़ाया। गाय ने इसके बाद भी लोगों को दौड़ाया था जिससे इलाके में दहशत फैल गई थी। आखिर कौन था इस गाय का

मालिक? इस वायरल वीडियो के बाद लखनऊ नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम ने तुरंत कार्रवाई की। काफी मशकत के बाद टीम ने न सिर्फ उस हमलावर गाय को पकड़ा, बल्कि आसपास खुली घूम रही 4 अन्य गायों और एक बछिया को भी पकड़ लिया। जांच में पता चला कि ये सभी गाय और बछिया मोहम्मद मुन्ना, मोहम्मद राजू और मोहम्मद छोटे नाम के लोगों की थीं। इन लोगों ने अपने पशुओं को खुले में छोड़ दिया था, जिससे यह घटना हुई। नगर निगम ने इन तीनों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। नगर निगम का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़े गए जानवरों का लोगों को घायल करना पब्लिक न्यूसेंस में आता है। पकड़ी गई सभी गायों और बछिया को कांजी हाउस में भेज दिया गया है।

एलडीए के सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मना प्रकृति पर्व



(जीएनएस)। लखनऊ। एलडीए के सीजी सिटी अर्बन वेटलैंड में मंगलवार को वेटलैंड डे के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण पर विविध कार्यक्रम हुए। सुबह बर्ड वॉचिंग से कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें स्कूली बच्चों और पर्यावरण प्रेमियों ने दूरबीन से पक्षियों का अवलोकन किया। विशेषज्ञों ने पक्षियों की प्रजातियों, उनके व्यवहार और वेटलैंड के परिस्थितिकी तंत्र में योगदान की जानकारी दी।

सेवानिवृत्त आईजी को भी एसआईआर नोटिस, बारिश के कारण कम पहुंचे लोग

(जीएनएस)। लखनऊ विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण कल्याण अधिकारी की ओर से सुनवाई के लिए 447 लोगों को नोटिस भेज कर मंगलवार बुलाया गया था, लेकिन सुबह बारिश के कारण कुल 65 लोग ही पहुंच सके। इनमें आईजी (फायर सर्विस) के पद से सेवा निवृत्त हुए इंदिरानगर निवासी 78 वर्षीय अभय शंकर भी शामिल रहे।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कुछ ऐसे लोगों को भी नोटिस मिला है जिनकी गिनती विशिष्ट, जागरूक व जिम्मेदार लोगों में होती है। सुबह बारिश के कारण सभी एसआईआर के पास काफी कम संख्या में लोग सुनवाई के लिए पहुंचे। इसके चलते अधिकांश स्थानों पर एसआईआर सुनवाई के लिए आने वाले लोगों की बात जोड़ते रहे।

विकास भवन स्थित जिला समाज कल्याण कल्याण अधिकारी की ओर से सुनवाई के लिए 447 लोगों को नोटिस भेज कर मंगलवार बुलाया गया था, लेकिन सुबह बारिश के कारण कुल 65 लोग ही पहुंच सके। इनमें आईजी (फायर सर्विस) के पद से सेवा निवृत्त हुए इंदिरानगर निवासी 78 वर्षीय अभय शंकर भी शामिल रहे। विकास भवन की लिफ्ट खराब होने

के कारण उन्हें भी सीढ़ियों के सहारे तीसरी मंजिल पर चल रही सुनवाई के लिए जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जो



आवेदन भरा था, उसमें मतदाता पहचान पत्र तो लगाया था, लेकिन 2003 की मतदाता सूची से उसका मिलान नहीं हो पाया था। जिसकी वजह से उन्हें नोटिस मिला। अब उन्होंने जो कमियां थी सभी पूरी कर दी है।

इसके अलावा इंदिरानगर निवासी उद्यान विभाग में कर्मचारी बी देवेंद्र भी सुनवाई के लिए पहुंचे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2003 में वह करीब 14 साल के थे लिहाजा उनका नाम मतदाता सूची में नहीं आ सका था। उसी वर्ष उनके पिता का निधन हो जाने के

कारण उनका भी नाम मतदाता सूची में नहीं था। मां का नाम था, जिसके अभिलेख लगाए थे, लेकिन इसके बाद भी नोटिस मिले। अब शैक्षिक

प्रमाणपत्र व कुछ अन्य दस्तावेज जमा किए हैं। हुसैनबाद ट्रस्ट में नोटिस की सुनवाई कर रहे जिला कृषि अधिकारी तेगबहादुर सिंह ने भी मंगलवार करीब 300 लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया था, लेकिन वहां भी कम ही लोग बारिश के कारण पहुंचे। जिले के अन्य स्थानों पर चर्चा रही सुनवाई की भी कमोवेश यही स्थिति रही।

नोटिस लक्ष्य 8.99 लाख, जारी 4.61 लाख जिले में मतदाता सूची से जुड़े सत्यापन अभियान के तहत अब तक 8,99,781 नोटिस जारी किए जाने का

टीएसए के निदेशक डॉ. शैलेन्द्र सिंह, अंबेडकर विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के एमए खालिद, लखनऊ विश्वविद्यालय की डॉ. अमिता कर्नौजिया व गोमती टास्क फोर्स के मेजर केएस नागी शामिल रहे। विशेषज्ञों ने वेटलैंड की भूमिका, भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और तापमान संतुलन पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से प्लास्टिक उपयोग कम करने और जल स्रोतों की रक्षा की अपील की।

लक्ष्य तय किया गया है। जिसमें मंगलवार तक 4,61,025 लोगों को नोटिस जनरेट किया जा चुका है। इनमें से 2,89,316 नोटिस संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं, जबकि 1,71,709 नोटिस अभी वितरण के लिए लंबित हैं। सबसे अधिक नोटिस बख्शी का तालाब, सरोजिनी नगर और लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में जनरेट हुए हैं। प्रशासन ने लंबित नोटिसों के शीघ्र वितरण के निर्देश दिए हैं ताकि सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

जिले भर में अब तक 93 हजार से अधिक मामलों की हुई सुनवाई मतदाता सूची से जुड़े नोटिसों पर चल रही सुनवाई प्रक्रिया के तहत जिले में अब तक 93,502 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 1,47,550 मामलों में सुनवाई की तारीख निकल चुकी (डेट लैप्स) दर्ज है। री-शेड्यूल (पुनर्निर्धारित) सुनवाई की संख्या 465 बताई गई है। लखनऊ पश्चिम में सबसे ज्यादा 22,227 सुनवाई हुई हैं, जबकि बख्शी का तालाब में 14,011 और लखनऊ उत्तर में 10,824 मामलों में सुनवाई दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटारा जा रहा है।

लखनऊ-कानपुर रोड पर डंपर-कंटेनर की टक्कर:2 घंटे तक भीषण जाम लगा, यातायात बाधित रहा

(जीएनएस)। लखनऊ। बंधरा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे के कारण कानपुर रोड पर करीब दो घंटे तक भीषण जाम लगा रहा। लखनऊ से कानपुर की ओर जा रहे एक डंपर में पीछे से आ रहे कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया।

यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे कटी बगिया के पास हुई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे उसके पीछे चल रहा कंटेनर अनियंत्रित होकर डंपर में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कंटेनर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त



हो गया। करीब दो घंटे तक यातायात पूरी

तरह ठप रहा हादसे के बाद डंपर चालक

अपना वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इस घटना में कंटेनर चालक को कोई चोट नहीं आई है। हादसे के कारण लखनऊ से कानपुर जाने वाली पटरी पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब दो घंटे तक यातायात पूरी तरह ठप रहा, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन रेंग-रेंग कर निकल रहे थे।

सूचना मिलने पर बंधरा पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। दोपहर करीब 12:30 बजे एक क्रैन मंगाकर क्षतिग्रस्त कंटेनर को सड़क के किनारे हटाया गया। इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका।

लखनऊ में 'पठन संस्कृति उत्सव':शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट ने किया आयोजन

(जीएनएस)। लखनऊ के राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में सोमवार को 'पठन संस्कृति उत्सव' का आयोजन किया गया। इस उत्सव ने विद्यालय परिसर को शिक्षा, साहित्य और कला के केंद्र में बदल दिया। यह आयोजन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली के सहयोग से संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में पठन, चिंतन तथा रचनात्मकता को संस्कृति को बढ़ावा देना था। अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, पार्थ सारथी सेन शर्मा के मार्गदर्शन में यह उत्सव आयोजित हुआ। उन्होंने पठन संस्कृति को शिक्षा की आत्मा बताते हुए इसे केवल एक औपचारिक आयोजन के बजाय विचार और संवाद के उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया। पठन संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है



पार्थ सारथी सेन शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उनका तथा उपस्थित रचनाकारों, लेखकों और साहित्यकारों का सम्मान किया गया। पुस्तकालय प्रकोष्ठ की विशेष कार्याधिकारी सांत्वना तिवारी ने कहा कि पठन संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है, जिसे विद्यालय, शिक्षक और

पुस्तकालय मिलकर ही सकारात्मक रूप दे सकते हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि पुस्तकें विद्यार्थियों को कक्षा की सीमाओं से परे व्यापक ज्ञान से जोड़ती हैं। उप शिक्षा निदेशक रेखा दिवाकर ने पठन

को व्यक्तित्व विकास की आधारशिला बताया। जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यालय को पुस्तक, कला और संवाद का केंद्र बनना चाहिए।

विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया

उत्सव के प्रथम सत्र में पार्थ सारथी सेन शर्मा ने पठन संस्कृति और वर्तमान शिक्षा सुधारों पर अपने विचार साझा किए द्वितीय सत्र में राष्ट्रीय कला उत्सव और स्कूल बौद्ध प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान वायलिन वादन, कथक और लोकनृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियां हुईं।

कथावाचक हिमांशु बाजपेई और वैष्णवी की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में भावनात्मक गहराई जोड़ी। मीडिया कोऑर्डिनेटर दिनेश कुमार ने बताया कि यह उत्सव इस संदेश के साथ संपन्न हुआ कि पुस्तकें समाज की चेतना और विवेक का आधार हैं।

लखनऊ में 31वां युवा साहित्यकार सम्मान समारोह:छह राज्यों से आए रचनाकारों को किया सम्मानित, 25 हजार रुपए की धनराशि दी

(जीएनएस)। लखनऊ के माधव सभागार, सरस्वती शिशु मंदिर, निराला नगर में पं. प्रताप नारायण मिश्र स्मृति 31वें युवा साहित्यकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारूवा देवराज सेवा न्यास की ओर से आयोजित किया गया। इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों से आए युवा साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी गोविंददेव गिरि महाराज थे, जबकि भूजल रिचार्ज, बाढ़ नियंत्रण और तापमान संतुलन पर प्रकाश डालते हुए नागरिकों से प्लास्टिक उपयोग कम करने और जल स्रोतों की रक्षा की अपील की।

लक्ष्य तय किया गया है। जिसमें मंगलवार तक 4,61,025 लोगों को नोटिस जनरेट किया जा चुका है। इनमें से 2,89,316 नोटिस संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं, जबकि 1,71,709 नोटिस अभी वितरण के लिए लंबित हैं। सबसे अधिक नोटिस बख्शी का तालाब, सरोजिनी नगर और लखनऊ पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों में जनरेट हुए हैं। प्रशासन ने लंबित नोटिसों के शीघ्र वितरण के निर्देश दिए हैं ताकि सत्यापन प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

जिले भर में अब तक 93 हजार से अधिक मामलों की हुई सुनवाई मतदाता सूची से जुड़े नोटिसों पर चल रही सुनवाई प्रक्रिया के तहत जिले में अब तक 93,502 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है, जबकि 1,47,550 मामलों में सुनवाई की तारीख निकल चुकी (डेट लैप्स) दर्ज है। री-शेड्यूल (पुनर्निर्धारित) सुनवाई की संख्या 465 बताई गई है। लखनऊ पश्चिम में सबसे ज्यादा 22,227 सुनवाई हुई हैं, जबकि बख्शी का तालाब में 14,011 और लखनऊ उत्तर में 10,824 मामलों में सुनवाई दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि लंबित मामलों को प्राथमिकता पर निपटारा जा रहा है।

लखनऊ में निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप:इलाज के बाद मरीज की मौत, परिजनों ने की शिकायत

(जीएनएस)। लखनऊ के दुबग्गा क्षेत्र स्थित एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा गया है। परिजनों का दावा है कि गलत इलाज और समय पर रेफर न करने के कारण 36 वर्षीय मरीज गंगा राम यादव की मौत हो गई। उन्होंने पुलिस और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इटौली गांव निवासी गंगा राम

लतीफी का शिकार हुई। गोरखधाम एक्सप्रेस सहित दो दर्जन से अधिक ट्रेनों घंटों लेट लतीफी का शिकार हुई। दिल्ली में सोमवार देर रात मौसम खराब हो गया था। श्रीनगर से दिल्ली जा रही उड़ान आइएक्स-

1029 रात 12:45 बजे लखनऊ डाइवर्ट हो गई। विमान में 161 यात्री और कर्ज के सदस्य सवार थे। विमान मौसम सही होने पर रात 1:30 बजे दिल्ली रवाना हो गया। मंगलवार को अचानक मौसम बिगड़ने के कारण दिल्ली से सुबह 9:40 बजे आने

वाली इंडिगो एयरलाइन की उड़ान 6ई -2107 समय से 50 मिनट लेट हो गई। इसी तरह बंगलुरु लखनऊ उड़ान 10:35 की जगह 11:47 बजे, एफजेड 443 दुबई- लखनऊ 10.50 की जगह 11:07 बजे आयी।

परिवार को जान से मारने, अपहरण की धमकी:लखनऊ में पुलिस से सुरक्षा की मांग

(जीएनएस)। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक परिवार को जान से मारने और अपहरण की धमकियां मिल रही हैं। छन्दौड़िया खेड़ा निवासी मोहम्मद कैफ ने पुलिस को शिकायत पत्र देकर अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। उनका आरोप है कि कुछ दबांग लगातार उन्हें और उनके परिवार को धमका रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद कैफ के अनुसार, दबांगों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही, उनके भतीजे को स्कूल के बाहर करीब 12:30 बजे एक क्रैन मंगाकर क्षतिग्रस्त कंटेनर को सड़क के किनारे हटाया गया। इसके बाद धीरे-धीरे यातायात सामान्य हो सका।

यादव को पैर में तेज दर्द के चलते 16 जनवरी को जॉर्जस पार्क स्थित विकल्प अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार, अस्पताल के डॉक्टर विवेक वर्मा ने ऑपरेशन कर पैर से सफाई कराई, लेकिन मरीज की हालत में सुधार नहीं हुआ। मरीज की हालत गंभीर हो गई करीब 15 दिनों तक इलाज चलने

के बावजूद गंगा राम की तबीयत लगातार बिगड़ती रही। परिजनों की मदद की है कि जब मरीज की हालत गंभीर हो गई, तो अस्पताल प्रबंधन ने उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह देकर डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद परिजन मरीज को पास के आग्रपाली अस्पताल ले गए, जहां से उसे मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। रविवार देर रात मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान गंगा राम यादव की मौत हो गई। खराब आर्थिक स्थिति के कारण जेवर तक बेचने पड़े मृतक की पत्नी रंजना यादव ने आरोप लगाया है कि विकल्प अस्पताल के प्रबंधक अभिषेक रस्तोगी ने इलाज के नाम पर करीब सात लाख रुपये वसूल लिए। उन्होंने बताया कि परिवार को अपनी खराब आर्थिक स्थिति के कारण जेवर तक बेचने पड़े। वहीं, विकल्प अस्पताल के प्रबंधक अभिषेक रस्तोगी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उनका कहना है कि मरीज से कुल डेढ़ लाख रुपये ही जमा किए गए थे। रस्तोगी के अनुसार, मरीज की हालत पहले से गंभीर थी और स्थिति बिगड़ने पर उसे उच्च संस्थान के लिए रेफर किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि दो दिन वीत जाने के बाद भी परिजनों की ओर से कोई औपचारिक शिकायत अस्पताल को नहीं मिली है। पुलिस कर रही मामले की जांच दुबग्गा थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्रीकांत राय ने जानकारी दी कि अभी तक थाने में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया कि शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।